(c) As on 30th June, 1995, one Cotton/ Man-made Fibre Textile Spinning Mill namely; M/s Lingaraj Textile Mill in Bhubaneswar is reported to be closed since 1.10.93 due to financial difficulties.

(d) and (e) The Government has established a Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) to evolve and manage rehabilitation packages in respect of viable sick/closed textile mills. The case of M/s Lingaraj Textile Mill is found to be not maintainable by BIFR.

Assessment of Power Production

283. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have assessed the effect of drought condition on power production in hydroelectric projects and thermal power projects, if so, the State-wise detials thereof; and

(b) what measures Government propose to overcome the short fall in the power availability?

THE MINSITER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILA CHIMANBHAI PATEL): (a) and (b) Almost all the reservoir levels are presently lower than what they were compared to last year. But, last year was an exceptionally good monsoon year and so the comparison may not be apt. Also, of late substantial inflows have started coming into the reservoirs and the levels are rising. This is an encouraging trend. there are precedents when lesser inflows during June/July were made up in August September. Hence, keeping in view the normal monsoon forecast by the Metrological Department, no serious deficiency is anticipated. The actual hydro and thermal generation exceeded the targets set for the period April-June, 1995. Relevent date is given below:—

	Generation Target	(MU) Actual	Percentage (%)
Hydro	16579	17762	(+) 7.1
Thermal	74071	74252	(+) 0.2

However, the situation is being monitored regularly and corrective measures would be taken if need.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत

284. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय कर्मचारी संघों ने सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अंतरिम राहत के प्रति अनिच्छा का दृष्टिकोण व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या आधार हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखरमूर्ति): (क) से (ग) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् में सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच सर्वसम्मति होने पर अंतरिम राहत की मंजूरी से सम्बन्धित प्रश्न पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को भेजा गया था। आयोग ने अपनी सिफारिशें देने से पूर्व कर्मचारी पक्ष के विचारों का भी पता लगाया था। तत्पश्चात् आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थीं। उनकी एक सिफारिश सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1.4.1995 से उनके मूल वेतन के 10% की दर से किन्तु कम से कम 100/- रुपय प्रतिमाह अन्तरिम राहत देने के बारे में है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इसे कार्यान्वित कर दिया है। तथापि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के एक वर्ग ने अन्तरिम राहत की मात्रा पर असंतोष व्यक्त किया है। पहले से स्वीकृत की गई अंतरिम राहत की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।